(b) if so, what are the findings of the Team about the dimension and intensity of the drought;

(c) what steps Government have taken to help the affected people of those areas; and

(d) what are the details of Central assistance asked for by the Maharashtra Government and that sanctioned by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (d) Government of Maharashtra had submitted a Memorandum seeking additional Central assistance of Rs. 789.41 crores for drought relief measures. A Central Team visited the State to assess the situation. After considering the Report of the Team, it has been decided that no additional Central assistance, over and above the provisions of the Calamity **Relief Fund is required to be provided, as** the situation in the State cannot be treated to be 'rare severity' warranting handling at the national level. However, in order to augment the resources of the State Government for relief measures, Central Government have released its entire share of Calamity Relief Fund for 1992-93 amounting to Rs. 33.00 crores in advance.

2. The relief measures undertaken by the State Government in the affected areas include:—

(i) Generation of additional employment;

(ii) Provision of drinking water in problem villages and towns;

(iii) Ensuring the availability of fodder;

(iv) Strengthening the Public Distribution system.

उत्तर प्रदेश में शुष्क भूमि पर कृषि

268. श्री ईश दत्त यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में शुष्क भूमि कृषि परियोजनायें कियान्वित की गई हैं और यदि हां, तो उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्षा-पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हिमालयी पनधारा प्रबंध परियोजना कार्यान्वित की गई है। जिलावार ब्यौरा विवरण–1 और विवरण–2 में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) चयनित पनधारा/शुष्क भूमि क्षेत्रों में कृषि, पशु पालन, सस्य-वानिकी, शुष्क भूमि बागवानी, घरेलू उत्पादन पद्धति आदि सहित पूरी कृषि पद्धति को बेहतर बनाकर पारिस्थितिक संसाधनों के अनुरूप सकल जैव समूह उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किये गये हैं।

विवरण–1

यह परियोजना 34 जिलों में स्थित 188 प्रखण्डों में सिंचाई के सुनिश्चित साधनों द्वारा सेवित उनके 30 प्रतिशत कृष्य क्षेत्र से कम में लागू की जा रही है। प्रत्येक प्रखण्ड में लगभग 500–5000 हैक्टैयर की एक पनधारा सतत विकास के लिए चुनी गई है। जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	जिले का नाम	प्रखण्ड/पनधाराओं की संख्या
1	2	3
1.	सहारनपुर	1
2.	आगरा	2
3.	बदायूं	2
4.	इटावा	1

1	2	3
5.	कानपुर	1
6.	फतेहपुर	3
7.	इलाहाबाद	4
8.	झांसी	7
9.	लेलितपुर	3
10.	जालौन	9
11.	हमीरपुर	9
12.	बांदा	8
13.	सोनभद्रा	7
14.	मिर्जापुर	3
15.	बलिया	6
16.	सिद्धार्थ नगर	4
17.	महराजगंज	2
18.	देवरिया	6
19.	खीरी	6
20.	गोंडा	12
21.	बहराइच	14
22.	सुल्तानपुर	1
23.	बाराबंकी	1
24.	जौनपुर	1
25.	आजमगढ़	1
26.	नैनीताल	4
27.	अल्मोड़ा	13
28.	पिथौरागढ़	11
29.	चमोली	11
30.	उत्तरकाशी	6
31.	टिहरी	9
32.	पौड़ी	14
33.	देहरादून	2
34.	सीतापुर	4
	कुल :	188

विवरण–2

उत्तर प्रदेश के तीन जिलों पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के चयनित पनधाराओं में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक चयनित पनधारा में वानिकी, मृदा संरक्षण, बागवानी, कृषि और पशु-पालन से संबंधित कार्यक्रम निरूपित और कार्यन्वित किये जा रहे हैं। जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

			क्षेत्र ("000" हैक्टेयर में)
क्रमांक	जिले का नाम	पनधारा का नाम	
1.	पौड़ी	नयार	265.6
2.	अल्मोड़ा	पनार	46.4
3.	पिथौरागढ़		
		कुल :	312.00

Financial assistance to drought affected State of Rajasthan

269. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that 21600 villages in Rajasthan having a population of about three crores are severely affected by drought;

(b) whether Government propose to send a Central Team to Rajasthan to assess the prevailing drought situation there;

(c) if so, the details of special assistance the Central Government propose to render to Rajasthan to meet the challenge;

(d) wheher the State Government of Rajasthan had sought, additional financial assistance from the centre to carry out relief operations besides creating of over 4 lakh mandays daily in the dronght affected areas in the State; and

(e) if so, to what extent Government have agreed to provide additional financial assistance to the State Government stating the reasons for not meeting the demand in full?